एशिया में सामुदायिक भूमि अधिकारों के साथ संरक्षण और वैश्विक जैव विविधता लक्ष्यों से तालमेल

रिपोर्ट का सारांश

अक्टूबर 2021 में दुनिया भर के नेताओं ने जैव विविधता (CBD) पर पन्द्रहवें महासम्मेलन (COP-15) की शुरुआत की ताकि संरक्षण की दिशा में उठाये जा रहे वैश्विक कदमों के भविष्य को परिभाषित किया जा सके।

उम्मीद की जा रही है कि मई 2022 में, जब यह प्रक्रिया समाप्त होगी, पार्टियां 2020 के बाद के वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (GBF) को अपना लेंगी। इस फ्रेमवर्क के तहत संरक्षण (कन्जर्वेशन) की कामयाबी को मापने के लिये जो प्रमुख अनुभवजन्य मानक रहे हैं, उनमें दुनिया की 30 प्रतिशत भूमि और इतने ही जल को आधिकारिक रूप से संरक्षित करने के महत्वाकांक्षी 30x30 जैसे स्थानिक लक्ष्य, शामिल हैं।

लेकिन संरक्षण के इस सरलीकृत विचार से दुनिया भर के आदिवासियों और स्थानीय सामुदायिक अधिकारों को लेकर चिंताएं उठ रही हैं।

ऐसे वातावरण में जहां लोगों की पहचान और उनके क्षेत्रीय अधिकारों को या तो मान्यता ही नहीं दी जाती या उनकी उपेक्षा की जाती है, वहां स्थानिक संरक्षण लक्ष्यों का कितना पालन होगा इसे लेकर मूलनिवासियों और सामुदायिक नेतृत्व में संदेह और चिंता रहती है।

यह समझने के लिए कि वैश्विक पर्यावरणीय लक्ष्य, जैसे 30x30, दुनिया भर में लगातार किस तरह बनाये और कार्यान्वित किए जा रहे हैं, हमें खुद संरक्षण के राजनैतिक और आर्थिक इतिहास पर एक गहरी दृष्टि डालने की आवश्यकता है।

इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि स्थानिक लक्ष्यों के बहाने ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सत्ता थोपने और नियंत्रण करने की कोशिश न हो और न ही उन लोगों के मानवाधिकारों की कीमत पर सार्वजनिक या निजी हितों को आगे बढ़ाया जाये जो कि इसकी मार झेलते हैं।

एशिया में, अक्टूबर 2021 तक, संरक्षित इलाके लगभग 15.37 प्रतिशत क्षेत्र (478.5 mHa) पर फैले हुए हैं।

कुल मिलाकर एक अरब से अधिक लोग या तो वर्तमान में इन संरक्षित क्षेत्रों में रहते हैं या इस क्षेत्र में जैव विविधता संरक्षण के लिए बड़े महत्व वाले क्षेत्रों में रहते हैं।

पंद्रह करोड़ लोग संरक्षित क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि अन्य 85.92 करोड़ गैर-संरक्षित जैव-विविध क्षेत्रों में रहते हैं, जो अतिरिक्त 23.8 प्रतिशत भू-भाग पर फैले हुए हैं।

यह क्षेत्र की आबादी का 23.3 प्रतिशत हिस्सा है और यह दर्शाता है कि इंसान और जैव-विविधता किस हद तक एक दूसरे से गुंथे हुये हैं।

जबकि संरक्षित क्षेत्रों से लोगों को हटा देना अक्सर वैश्विक संरक्षण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सबसे प्रचलित और कारगर तरीका माना जाता है। हालांकि साक्ष्यों देखने से पता चलता है कि **स्थानीय लोगों और समुदायों द्वारा शासित, प्रबंधित और संरक्षित क्षेत्र और इलाके संरक्षण और टिकाऊ और समावेशी शासन का प्रभावी स्वरूप हैं।**

यह समुदाय उस प्राकृतिक संसाधन प्रणाली के प्रबंधन, बहाली और संरक्षण में औसतन $3.57 प्रति हेक्टेयर का निवेश करते हैं जिस पर वह निर्भर हैं, जो विश्व स्तर पर लगभग 5 बिलियन (500 करोड़) डॉलर सालाना है। यह रकम दुनिया भर में सरकारों, दानदाताओं, फाउंडेशन्स और गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा संरक्षण के लिये किये गये कुल विश्वव्यापी खर्च के एक चौथाई के बराबर है।।

इस कारण मूल निवासी (आदिवासी) और स्थानीय समुदायों की भूमिका संरक्षण के क्षेत्र में अग्रणी हो जाती है। ये दूसरी बात है कि निर्णायक भूमिकाओं में वही लोग अपने प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष कर रहे हों।

इस रिपोर्ट में ये तर्क दिये गये हैं कि जलवायु परिवर्तन और जैव-विविधता को हो हानि को प्रभावी ढंग से और समावेशी तरीके से कम करने के लिए संरक्षण के नये तौर-तरीकों की आवश्यकता है, जो लोगों को संरक्षित क्षेत्रों से हटाने की रणनीति का अंत करें, मानवाधिकार-आधारित रणनीतियों को अपनाएं और मूल निवासियों और स्थानीय समुदायों -- जो दुनिया की आधी से अधिक भूमि के मालिक हैं -- के भूमि, जंगल, पानी और क्षेत्रीय अधिकारों की मान्यता के लिए प्रयास करें।

हमने रिपोर्ट में यह भी प्रदर्शित किया है लोगों से उनकी भूमि और संसाधन छीनकर प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का सीबीडी विजन 2050 साकार नहीं होगा। बल्कि भूमि-उपयोग के सभी निर्णयों में प्रकृति के साथ सामंजस्य अंततः मानव अधिकारों और अंतर-पीढ़ीगत समानता की मान्यता पर टिका है।

2020 के बाद के संरक्षण एजेंडा में इस तरह के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, भविष्य की कार्रवाई और निवेशों को संरक्षण में जमीनी स्तर के समुदायों के नेतृत्व को पहचानना होगा और सफलता के माप के रूप में उनके भूमि अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान के विकास को प्राथमिकता देनी होगी।

संरक्षण में मूल निवासियों और स्थानीय समुदायों का महत्व

दुनिया भर में मूल निवासी और स्थानीय समुदाय लंबे समय से जैव-विविधता के संरक्षक रहे हैं। उनके परम्परागत क्षेत्रों में दुनिया के शेष अक्षुण्ण वन परिदृश्य का 36 प्रतिशत और शेष जैव विविधता का 80 प्रतिशत होने का अनुमान है। इन क्षेत्रों के भीतर जैव-विविधता की व्यापकता का सीधा संबंध प्रथागत अधिकार धारकों के समुदायों के प्रभावी शासन से है। **वैश्विक डेटा दर्शाता है कि मूलनिवासी और सामुदायिक अधिकार धारकों की भूमि पर वनों की कटाई की दर कम है, वहां अधिक कार्बन स्टोर होता है, और सरकारी या निजी संस्थाओं द्वारा प्रबंधित भूमि की तुलना में अधिक जैव-विविधता है।**

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, 90 से अधिक देशों में 476 मिलियन (47.6 करोड़) मूल निवासी -- या वैश्विक जनसंख्या का 6.2 प्रतिशत -- रहते हैं। क्षेत्रीय मूलनिवासी संगठनों के अनुसार, जो जनसांख्यिकीय विश्लेषण भी करते हैं, अकेले एशिया में 411 मिलियन (41.1 करोड़) मूलनिवासी हो सकते हैं। इन आंकड़ों में गैर-मूलनिवासी स्थानीय और पारंपरिक समुदाय शामिल नहीं हैं। इन समाजों में विविधता को एशिया में राष्ट्रीय कानूनों में प्रभावी रूप से मान्यता नहीं दी गई है, और जहां दी गई है वहां सुरक्षा उपायों को पर्याप्त रूप से लागू नहीं किया गया है। मूलनिवासी प्रथागत संस्थानों और स्वशासन प्रणालियों की कानूनी मान्यता न होने के साथ-साथ उनके पैतृक प्रथागत क्षेत्रों पर उनके भूसंपत्ति अधिकार भी सुरक्षित नहीं हैं। **आरआरआई के अनुसार, मूलनिवासियों और स्थानीय समुदायों के स्वामित्व वाले क्षेत्र का केवल 8.7 प्रतिशत ही कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है**।

जैव-विविधता की रक्षा करने वाले मूलनिवासियों के मूल्यवान योगदान के पीछे हैं उनका समावेशी वैश्विक दृष्टिकोण, उनकी सार्वभौमिकता, उनकी सुपरीक्षित प्रथाएं, और उनके अंतर-पीढ़ी ज्ञान प्रणालियों के माध्यम से व्यक्त किए गए संबंधपरक मूल्य। हर समुदाय अपने बनाये नियमों, पारंपरिक संस्थानों और समावेशी तौर तरीकों के साथ अपने आसपास के पर्यावरण से तालमेल बिठाता है। यदि राष्ट्रीय सरकारें इन्हें अपने बसेरों से हटा देंगी और पश्चिमी संरक्षण के तौर-तरीके थोपेंगी तो यह कारगर नहीं होगा और इन क्षेत्रों में पहले लागू किये गये औपनिवेशिक तौरतरीकों को आगे बढ़ाने जैसा ही होगा। यहां तक कि अधिक समतावादी माने जाने वाली आईयूसीएन (IUCN)-संरक्षित क्षेत्र श्रेणियां (श्रेणियां IV, V, और VI जो संसाधन उपयोग या प्रबंधन के लिए मार्ग दिखती हैं) इन क्षेत्रों का प्रबंधन करने वाले समुदायों के बजाय मुख्य रूप से सरकारी नुमाइंदों द्वारा शासित होती हैं।

खतरे में है ज़मीनी स्तर पर संरक्षण से जुड़ा नेतृत्व

प्रमुख संरक्षण संगठनों द्वारा 2021 की तकनीकी समीक्षा के अनुसार, **25 प्रतिशत से अधिक पारंपरिक क्षेत्रों को अब वैश्विक स्तर पर कमोडिटी-संचालित विकास से खतरा है**। इन क्षेत्रों में संग्रहीत अधिकांश कार्बन, यदि एक बार बड़े पैमाने पर कटाई, कृषि, खनन, और अन्य प्रक्रियाओं से होने वाली वन हानि और भूमि उपयोग और भूमि आच्छादन परिवर्तन के कारण निकल गया, तो उसे फिर खतरनाक जलवायु और जैव-विविधता प्रभावों से बचने के लिए आवश्यक समय-सीमा पर फिर से सोखना संभव नहीं होगा।

यह समुदाय अपने संरक्षण नेतृत्व का प्रदर्शन राजनैतिक संघर्षों के माध्यम से करते हैं जिनका उद्देश्य पैतृक ज्ञान और प्रथागत संस्थानों को संरक्षित करना, लिंग-संवेदनशील और समावेशी प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना और उनके मौलिक मानवाधिकारों और पहचान को मान्यता देने वाले सुधारों या कानूनों हेतु प्रयासों का व्यापक पैमाने पर समर्थन करना है। **अपने अधिकारों के लिए खड़े होने के कारण एशिया में जमीनी स्तर के नेताओं पर बार-बार खतरा मंडराता रहता है** और उन्हें अपने अधिकारों और पारितंत्र की अखंडता की रक्षा के लिए अधिकारियों, और उद्योग से जुड़े लोगों द्वारा हमेशा निशाना बनाया जाता है।

कुल मिलाकर, यह क्षेत्र उस प्रकार के राजनैतिक वातावरण का प्रतीक है जो मानवाधिकारों की कीमत पर व्यवसायियों और कंपनियों का पक्ष लेता है। सरकारें अक्सर ग्रामीण इलाकों पर रणनीतिक नियंत्रण हासिल करने के लिए संरक्षित क्षेत्रों का सहारा लेती हैं और पर्यावरणीय हानि की भरपाई किसी और जगह करती हैं। पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और मानवाधिकारों को आर्थिक विकास के लिए बाधा माना जाता है और व्यावसायिक हितों को साधने के लिए उनकी अनदेखी की जाती है। कोविड - 19 महामारी के दौरान ये चुनौतिया बढ़ीं फिर भी समुदायों ने अत्यधिक सहनशक्ति का प्रदर्शन किया है।

आगे का रास्ता

जलवायु और जैव-विविधता के दोहरे संकट से जूझने के लिए मूलनिवासियों और स्थानीय समुदायों के अधिकारों की पूर्ण मान्यता और सुरक्षा पर ध्यान देना ज़रूरी है। यह मान्यता उनके अभिकरण, स्वायत्तता, पारंपरिक प्रथाओं और पैतृक ज्ञान को सशक्त बनाने का एक साधन है जो उनके अनुकूली पर्यावरणीय योगदान की धुरी हैं।

जैव-विविधता से भरपूर भूमि पर मूलनिवासी और सामुदायिक शासन को बढ़ावा देने पर होने वाला खर्च उस वित्तीय बोझ का अंशमात्र ही होगा जो आमतौर पर अपनाये जा रहे तरीकों से पड़ता है। मूलनिवासी और स्थानीय समुदाय पहले से ही अपने पैतृक और पारंपरिक क्षेत्रों के संरक्षण में सक्रिय हैं। वह उन प्राकृतिक संसाधन प्रणालियों के प्रबंधन, बहाली और संरक्षण में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से योगदान देते हैं जिस पर वह और दूसरे लोग निर्भर हैं। विस्थापन की स्थिति में समुदायों को फिर से बसाने और क्षतिपूर्ति करने और मौजूदा सामुदायिक संरक्षण प्रथाओं को बदलने की अनुमानित लागत, उनके भूसंपत्ति अधिकारों को मान्यता देने की लागत से 100 से 1,000 गुना अधिक हो सकती है। इसकी अनुमानित लागत **भारत** में 312.6 मिलियन (31.26 करोड़) अमरीकी डॉलर, **इंडोनेशिया** में 200 मिलियन (20 करोड़) डॉलर और **नेपाल** में 23.1 (2.31 करोड़) मिलियन डॉलर है।

हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए तमाम सेफगार्ड्स विकसित किए गए हैं कि संरक्षणकर्ता मूलनिवासियों और स्थानीय समुदायों के भूमि और संसाधन अधिकारों का सम्मान करें, लेकिन वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त ऐसे सिद्धांतों का अभाव जो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों पर आधारित हों और स्वयं अधिकार धारकों के सहयोग से विकसित किए जाएं।

संरक्षण प्रयासों के लिए भूमि अधिकार मानकों (**Land Rights Standard**) को अपनाना और उनसे तालमेल बिठाना एक प्रभावी समाधान हो सकता है। भूमि अधिकार मानकों का पालन करना भूदृश्य की बहाली, प्रबंधन, संरक्षण, क्लाइमेट एक्शन और विकास परियोजनाओं और कार्यक्रमों में मूलनिवासियों और स्थानीय समुदायों के भूमि और संसाधन अधिकारों को मान्यता और सम्मान देने के लिए एक स्पष्ट और सर्वोत्तम प्रणाली प्रदान करते हैं।

अनुशंसित उद्धरण: Asia Indigenous Peoples Pact, Badan Registrasi Wilayah Adat, Cambodian Indigenous Peoples Alliance, Cambodia Indigenous Peoples Organization, Centre for Orang Asli Concerns, Center for Indigenous Peoples' Research and Development, Federation of Community Forestry Users Nepal, Indigenous Media Network, Indigenous Peoples Foundation for Education and Environment, Indigenous Peoples Partnership, Indonesian Institute for Forest and Environment, Inter Mountain Peoples Education and Culture in Thailand Association, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, Land Conflict Watch, Nepal Federation of Indigenous Nationalities, Network of Indigenous Peoples in Thailand, Non-Timber Forest Products - Exchange Programme, Partners of Community Organizations in Sabah Trust, Promotion of Indigenous and Nature Together, Rights and Resources Initiative, and Working Group ICCAs Indonesia. 2021. Reconciling Conservation and Global Biodiversity Goals with Community Land Rights in Asia. Rights and Resources Initiative, Washington, DC.

लेखकों

भागीदारों

प्रायोजकों

यहां प्रस्तुत विचार आवश्यक रूप से उन एजेंसियों द्वारा साझा नहीं किए गए हैं जिन्होंने उदारतापूर्वक इस काम का समर्थन किया है, न ही आरआरआई गठबंधन के सभी भागीदारों और संबद्ध नेटवर्क द्वारा। यह कार्य क्रिएटिव कॉमन्स एट्रिब्यूशन लाइसेंस के तहत लाइसेंस प्राप्त है CC BY 4.0.

2715 M St NW, Suite 300, Washington, DC 20007